भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1618
02 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषयः किसानों की आय में वृद्धि

1618. श्री दीपक बैजः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आधुनिक तकनीकियों के माध्यम से जिनके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से किसानों को फसल, मौसम और कीटों संबंधी सटीक सूचना प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) सरकार का किन फसली मौसमों से किसानों को सूचना प्रदान करने का विचार है ताकि किसान ओलावृष्टि, पाला, कीडे-मकौड़ों के हमले से निपटने में समर्थ हो सके; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): जी, हां। सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित मुद्दों की जांच करने और वर्ष 2022 तक वास्तविक रूप से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक रणनीति की सिफारिश करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है।

समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्वीकारा है, जो ग्रामीण भारत को अपने कृषि कार्यकलापों को और आधुनिक बनाने और उसे संगठित करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है। प्रौद्योगिकियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि शामिल हैं। आधुनिक/उन्नत प्रौद्योगिकियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके और किसानों को फसलों, मौसम और कीड़ों आदि के बारे में सटीक और समय पर जानकारी देकर फसल उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है, जोखिम को कम किया जा सकता है और किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। प्रमुख प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) महत्वपूर्ण मापदंडों अर्थात् मौसम; बाजार मूल्य; पौध - संरक्षण; इनपुट डीलर (बीज, कीटनाशक, उर्वरक) फार्म मशीनरी; प्रतिकूल मौसम अलर्ट; मृदा स्वास्थ्य कार्ड; कोल्ड स्टोरेज और गोदाम; पशु चिकित्सा केंद्र और नैदानिक प्रयोगशाला के संबंध में किसानों को सूचना सुविधा प्रदान करने के लिए किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन का विकास। मंडी की जानकारी होने से किसानों को उपज बेचने के लिए, बाजार की मौजूदा कीमतों और बाजार में मांग की गई मात्रा के बारे में बेहतर जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार, वे उचित मूल्य और सही समय पर उपज बेचने के लिए सही निर्णय ले सकते हैं।

(ii) 'भारत में विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए फार्म मशीनरी पैकेज' का मोबाइल एप्लिकेशन विकास, जो राज्य-वार, कृषि-जलवायु क्षेत्र वार, जिलेवार, फसल पैटर्न के अनुसार और बिजली स्रोत-वार हेतु उपलब्ध कृषि मशीनरी पैकेज की जानकारी देता है।

(iii) किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विकसित फसलोपरांत प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मशीनरी के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए 'माई सिफेट' मोबाइल एप्लिकेशन का विकास।

(iv) आईसीएआर ने आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा विकसित 100 से अधिक मोबाइल एप्लिकेशन भी संकलित किए हैं और अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। फसलों, बागवानी, पशु चिकित्सा, डेयरी, कुक्कुट पालन, मात्स्यिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और एकीकृत विषयों के क्षेत्रों में विकसित किए गए ये मोबाइल ऐप किसानों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें पद्धति पैकेज, विभिन्न जिंसों के बाजार मूल्य, मौसम से संबंधित जानकारी, परामर्श सेवाएं आदि शामिल हैं।

(v) एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत किसानों को विभिन्न फसलों से संबंधित सलाह भेजने के लिए एमकिसान पोर्टल (www.mkisan.gov.in) का विकास।

(vi) किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए ई-राष्ट्रीय कृषि मंडी पहल की शुरूआत।

(vii) 2 साल के चक्र में एक बार देश भर के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरूआत। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को फसल उत्पादकता और मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक संबंधी सिफारिशों के साथ उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति की जानकारी प्रदान करता है।

(viii) फसल वर्गीकरण और क्षेत्र के आकलन के लिए अलग-अलग कंप्यूटर एल्गोरिथ्म के साथ मशीन लर्निंग प्रक्रिया का उपयोग करना।

सरकार ने कृषि समुदाय के बीच प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए जिला स्तर पर 713 कृषि विज्ञान केंद्र और 684 कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों की स्थापना की है। इसके अलावा, किसानों को केंद्रित प्रचार अभियान, किसान कॉल सेंटर, कृषि-क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय उद्यम केंद्रों, कृषि मेलों और प्रदर्शनियों, किसान एसएमएस पोर्टल इत्यादि के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाती है।

****